मजदूरों का अपना कोई देश नहीं होता । दुनियाँ के मजदूरो, एक हो !

फरीदाबाद मजदूर समाचार

मजदूरों की मुक्ति खुद मजदूरों का काम है । दुनियां को बदलने के लिए मजदूरों को खुद को बदलना होगा ।

RN 42233 पोस्टल रजिस्ट्रेशन L/HR/FBD/73

नई सीरीज नम्बर 51 | सितम्बर 1992 | 50 पैसे

यूनियन चुनाव

पिछले अंक में हमने यूनियन चुनाव के बारे में एक फैक्ट्री मजदूर की बातें रखी थी । यहां हम कलकत्ता में हिन्दुस्तान लीवर की फैक्ट्री में यूनियन चुनाव को लेकर हुई खींचा-तान का जिक्र करेंगे । सामग्री हमने कलकत्ता की 'श्रमिक इस्तेहार' बुलेटिन (जून ९२) से ली है ।

घटना के बैक ग्राउन्ड के लिये अप्रैल ९० के हमारे अंक पर एक नजर ,- हिन्दुस्तान लीवर मैनेजमेंट ने बम्बई फैक्ट्री में लम्बी तालाबन्दी करके मजदूरों के मजबूत संगठन को दबाया । कलकत्ता फैक्ट्री में मैनेजमेंट की पाकेट यूनियन थी पर जुलाई ८७ यूनियन चुनावों में जुझारू मजदूर चुने गये । मैनेजमेंट ने नये चुने लोगों को मान्यता नहीं दी । चुने हुये कोर्ट गये । अगस्त ८८ में मैनेजमेंट ने सीटू+इन्टक के पराजित लोगों की कमेटी बना कर उसे मान्यता दे दी । कलकत्ता हाई कोर्ट ने फिर चुनाव का फैसला दिया और इसके लिये २० अक्टूबर ८९ की तारीख निश्चित की । हिन्दुस्तान लीवर मैनेजमेंट ने चुनाव नहीं होने दिये । हाई कोर्ट ने तब २८ जनवरी ९० को चुनाव करवाने को कहा । बंगाल पुलिस-प्रशासन के सहयोग से मैनेजमेंट ने फिर यूनियन चुनाव नहीं होने दिया । साथ ही मैनेजमेंट ने २७ परमानेन्ट और ३०० ठेका मजदूर निकाल दिये ।

कलकत्ता हाईकोर्ट यूनियन चुनाव के लिये नई-नई तारीखें तय करता रहा और हिन्दुस्तान लीवर मैनेजमेंट कभी लक्स-लाइफबाय-रिन से उन्हें धोती रही, कभी डालडा में तलती रही, तो कभी रेड लेबल की चुस्कीयों के साथ पीती रही । इस प्रकार यूनियन चुनाव के लिये तय की गई सातवीं तारीख (१६ अगस्त ९१) भी गाजे-बाजे के साथ गुजर गई । लेकिन ठोकर पर ठोकर मारे जाने पर भी हिन्दुस्तान लीवर के मजदूरों ने नाक नहीं रगड़ी और टाइम-ब-टाइम अपना विरोध जाहिर करते रहे । २३ नवम्बर ९१ को कम्पनी के डायमन्ड जुबली फंक्शन का मजदूरों ने बायकाट किया और हिन्दुस्तान लीवर चेयरमैन को कुर्सियों को भाषण सुनाना पड़ा । मजदूरों के अड़ियल रूख से बंगाल सरकार की भी अधिकाधिक बदनामी होने लगी । और फिर, हाई कोर्ट की कुछ तो लाज रखनी थी -आखिर द्रोपदी के तन पर चिथड़े छोड़ने जरूरी जो हैं । कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा आठवीं बार तय तारीख, ८ मई ९२ को हिन्दुस्तान लीवर में यूनियन चुनाव हुये । मैनेजमेंट के मान्यता प्राप्त पैनल को ३१ वोट पड़े । एक पुराने लीडर के पैनल को एक सौ ग्यारह वोट पड़ें । जुझारू मजदूरों के पैनल को ६४६ वोट पड़े और उनके सब, २१ उम्मीदवार जीत गये ।

मजदूरों के धीरज-दीर्घकाल तक अड़े रहने का एक और उदाहरण हिन्दुस्तान लीवर की कलकत्ता फैक्ट्री के मजदूरों ने प्रस्तुत किया है ।

इस सिलसिले में कुछ बातें हैं जिन पर विचार करना जरूरी है—
१. हिन्दुस्तान लीवर की कलकत्ता फैक्ट्री के मजदूरों को अब तक अकेले जूझना पड़ा है । इस वजह से यूनियन चुनाव के मामले में ही बहुत दिक्कतें उन्हें उठानी पड़ी हैं । वेतन, वर्क लोड व वर्किंग कंडीशन जैसे क्षेत्रों में मैनेजमेंट से टक्कर लेने के लिये तो मजदूरों को और भी अधिक ताकत चाहिये । अकेले लड़े हिन्दुस्तान लीवर की बम्बई फैक्ट्री के मजदूरों को तालाबन्दी करके मैनेजमेंट ने पराजित किया था । ऐसे में आज कलकत्ता स्थित हिन्दुस्तान लीवर फैक्ट्री मजदूरों के लिये यह और भी जरूरी है कि वे अपनी ताकत बढाने वाले कदमों पर विचार करें । एक कदम है आस-पास की फैक्ट्रियों के मजदूरों से अनुभवों का आदान-प्रदान करके एक मजदूर मंच का गठन करना । इससे मजदूर पक्ष की ताकत बढ़ेगी

२. साझे मीटिंगों तथा आम सभाओं में विचार-विमर्श के सिलसिले के जरिये मजदूरों की पहलकदमी तथा कन्ट्रोल बनाये रखना ।

३. नेता और मजदूरों के पारम्परिक रिश्तों के सन्दर्भ में पिछले अंक में चर्चा हो चुकी है । नेता मशीन पर काम नहीं करेंगे, सोचने-फैसले लेने का काम नेता करेंगे, मजदूरों का काम चन्दा देना और नेताओं के हुक्म मानना है आदि-आदि वाले पुराने ढर्रे पर हिन्दुस्तान लीवर के मजदूर चले तो वे भी खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली बात ही दोहरायेंगे ।

पुलिस फायरिंग

नागपुर के पास राजूर कोयला खदान असुरक्षित है । पिछले दो साल में एक्सीडेन्टों में उसमें चार मजदूरों की मौत हुई । सेफ्टी के लिये मजदूरों ने कई बार वहाँ काम बन्द करने की मांग की पर मैनेजमेंट नहीं मानी । राजूर कोयला खदान सरकारी है ।

इस २० जुलाई की रात राजूर कोयला खदान में फिर एक्सीडेन्ट हुआ । खदान की छत गिरी और दो-तीन टन कोयले में दब कर एक मजदूर मर गया ।

मजदूरों की जिन्दगियों से ऐसे खिलवाड़ के खिलाफ मजदूरों का गुस्सा भड़का और.. और २१ जुलाई को पुलिस ने गोलियों से दो और मजदूर मार डाले ।

महाराष्ट्र सरकार ने एक तरफ पुलिस फायरिंग को गैरकानूनी आदि करार दे कर थानेदार समेत कई सिपाहियों को सस्पैन्ड किया और दूसरी तरफ राजूर में कर्फ्यू-स्पेशल पुलिस-गिरफ्तारियों वाला दमन-आतंक का माहौल बना कर दो हजार कोयला खदान मजदूरों को कुचलने के लिये कदम उठाये । मन्त्री और उनके भाई-बन्द अखबारी बयानबाजी में पुलिस फायरिंग की निन्दा कर रहे हैं और जारी दमन-चक्र पर गान्धी के बन्दर बने हैं... ।

राजूर में मजदूरों पर दमन-आतंक के खिलाफ नागपुर में 'दमन विरोधी कृति समिति' ने आवाज उठाई है । उपरोक्त सामग्री हमने उनके एक पर्चे से ली है ।

अबोहर पंजाब में कपड़ा मजदूरों पर पुलिस फायरिंग—डाला उत्तर प्रदेश में सीमेन्ट मजदूरों पर पुलिस फायरिंग —धनबाद बिहार में कोयला खदान मजदूरों पर पुलिस फायरिंग— भिलाई मध्यप्रदेश में इंजिनियरिंग व केमिकल मजदूरों पर पुलिस फायरिंग —नागपुर महाराष्ट्र में मेटल वरकरों पर पुलिस फायरिंग— ... क्या एक फैक्ट्री या एक क्षेत्र के मजदूर इन हमलों का मुकाबला कर सकते हैं ? अगर नहीं तो सोचिये : क्या करें ?

कमजोरी और ताकत

मुजेसर और आटोपिन झुग्गियों के बीच तालाब तथा खाली जमीन हैं जो कि इन दो इलाकों के बाशिन्दों के काम आते हैं । इमरजैन्सी के वक्त झुग्गियाँ तोड़ कर जमीन खाली करवाई गई थी—पुलिस फायरिंग, खून-खराब हुआ था । अब उस जमीन पर पुलिस-प्रशासन की मद्द से कबाड़िये कब्जा कर रहे हैं ।

टट्टी-पेशाब की जगह पर इन कब्जों ने आटोपिन झुग्गियों की तकलीफें और बढा दी हैं । कब्जा करने वाले औरतों तक से रोज तू-तड़ाक करते हैं । तंग आकर कुछ औरतों ने इकट्ठी हो कर एक कबाड़िये के टीन-टप्पर पर थोड़ी दस्तक दी ।

अच्छे-खासे पैसे कमा रहा कबाड़िया मुजेसर थाने के एक कर्मचारी को लेकर पहली अगस्त की शाम को आटोपिन झुग्गियों में आ धमका । पुलिसवाले ने दो झुग्गीवासियों को पकड़ा और मारता-पीटता उन्हें थाने ले जाने लगा । कुछ समय तक सकपकाये लोग खड़े-खड़े देखते रहे । पुलिसवाले और कबाड़ी को छाती ताने दो झुग्गीवासियों को हांकने देख अहिस्ता अहिस्ता लोग जुटने लगे । औरतें आगे आई । मामला बिगड़ते देख पुलिसवाला पकड़े हुये लोगों को थ्रीव्हीलर में डाल कर थाने भागा— इसमें कुछ बिचौलियों ने उसकी मद्द की ।

पुलिसवाले और कबाड़िये की इस गुन्डागर्दी से निपटने के लिये एकजुट होते झुग्गीवाले मुजेसर थाने की ओर चल दिये । लोगों की तादाद बढती गई । औरतें आगे-आगे थीं । थाने पहुँचते-पहुँचते सैकड़ों लोग हो गये और भीड़ बढने लगी ।

इक्के-दुक्के से गाली-थप्पड़-मुक्के-डन्डे से बात करना जिनका चरित्र हैं वे ही लोगों के समूह को देख कर ठन्डे पड़जाते हैं । लोगों की भीड़ पुलिस को बला नजर आती है । आटोपिन झुग्गियों वाली बला टालने में मुजेसर थाने ने आधा घन्टा भी नहीं लगाया—बिना पूजा भेंट के चुपचाप पुलिस ने हिरासत में लिये दोनों झुग्गिवासियों को छोड़ दिया ।

मजदूरों का गुस्सा

फोर्ट बिलियम जूट मिल मैनेजमेंट द्वारा गुप-चुप तालाबन्दी करने से १८ जुलाई को हावड़ा के शिवपुर क्षेत्र में मजदूर भड़क उठे । गुस्से से भरे दो हजार मजदूरों ने स्टाफ क्वाटरों व चीफ एग्जेक्यूटिब के बँगले पर धावा बोला तथा इलाके की सड़कें तो जाम की ही, लाल झन्डे को पूजते आ रहे इन मजदूरों ने लोकल सीटू लीडर के घर पर भी धावा बोला । सीटू लीडर की मोपेड और टी वी तथा ज्योति बसु और प्रमोद दास गुप्ता की तस्वीरें मजदूरों के गुस्से का शिकार बनी ।

लाकआउट, ले आफ और छँटनी के रूप में बंगाल में भी मजदूरों पर मैनेजमेंटों के हमले बढ रहे हैं और ... और ज्योति बसु अपनी सालाना महीने-भर की छुट्टी यूरोप में मना रहे हैं ।

[सामग्री हमने "इकानोमिक एन्ड पोलिटिकल वीकली' के २५ जुलाई ९२ अंक से ली है ।]

छोटे-छोटे कदम

१९९१ के हफ्ता ३२ से फैक्ट्री में खींचा-तान होने पर फरीदाबाद बाटा मैनेजमेंट रेटेड कैपेसिटी से ज्यादा प्रोडक्शन देने पर भी मजदूरों का डी ए काटती आ रही है । इसके खिलाफ ७५० बाटा मजदूरों ने अगस्त ९२ में दस्तखत करके मैनेजमेंट से काटे हुये डी ए के पैसे लौटाने की डिमान्ड की है ।

इस मुजेसर थाने के ही आठ-दस कर्मचारी थे जो जन्माष्टमी की रात साढे दस-ग्यारह बजे श्मशान के पास सड़क पर एक ट्रक ड्राइवर को मारते-पीटते रहे और पाप पर पुण्य को जीत दिलाने वाले की झांकियाँ देख कर आने वालों को चलते बनने के लिये हाँकते रहे थे । एक को आठ-दस से पिटते देख कर धर्मनिष्ठ भी और अधर्मी भी नाक की सीध में चलते रहे थे क्योंकि इकट्ठे होने का होश नहीं था और एकजुट हुये बिना पुलिस के मुंह कौन लगे.. ।

संपर्क - मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, बाटाचौक के पास, एन. आई. टी. फरीदाबाद 121001

एक पत्र

फरीदाबाद समाचार पत्र अकस्मात मेरे हाथ लगा। स्वयं एक ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता होने के कारण सबसे पहले मेरी निगाह "एक फैक्ट्री मजदूर की कलम से यूनियन चुनाव" लेख पर पड़ी। मन में आया कि इस मजदूर साथी से दो बातें कर लूँ।

मजदूर साथी ने जो अनुभव किया हैं वह पूर्णतय सत्य हैं परन्तु इसका उत्तर तो इसी पत्र के ऊपर लिखा हुआ है: 'दुनिया को बदलने के लिये मजदूरों को खुद को बदलना होगा।"

मैं जानता हूँ और देखा है कि एक-दो नही सैकड़ों यूनियनें वह नेता चला रहे हैं जो किसी कारण फैक्ट्रियों से निकाले गये हैं। सात व्यक्तियों के नाम देकर और किसी भी मान्यता प्राप्त यूनियन का संविधान लिख कर यूनियन खड़ी कर लेना कोई बड़ी बात नहीं। उन नेताओं की गर्म तकरीरें और धुँआधार भाषण सुन कर हम मजदूर ही मूर्ख बन जाते हैं। समझते है कि अब हमें कोई अच्छा नेता मिला है। हम यह नहीं सोचते कि यह अनपढ़ नेता मैनेजमेन्ट के योग्य कर्मचारियों के सम्मुख खड़े हो भी सकेंगे या अपने हलवे-माण्डे तक ही सीमित रहेंगे। मैनेजमेन्ट को ऐसे मजदूर नेताओं की जरूरत होती है क्योंकि उन्हें खरीदना सुगम होता है। मैनेजमेन्ट का यही हथियार भयानक है जिससे वह जब चाहे अपना काम ले लेता है। ऐसे नेताओं से ही वार्तालाप होती हैं और उन्हीं के साथ इच्छा अनुसार समझौता होता है। ऐसा होता आया है, हो रहा है परन्तु होता रहेगा यह मैं नहीं मानता।

३० वर्ष ट्रेड यूनियन के कार्य में रत रहने के पश्चात मैं इसी परिणाम पर पहुँचा हूँ कि मैनेजमेन्ट और इन स्वार्थी नेताओं की मार से बचने का केवल एक ही रास्ता है और वह यह है कि मजदूरों को जागना होगा, अपनी शक्ति को पहचानना होगा। स्वयं बदल कर सौरों को बदलना होगा। तभी मजदूर संगठित होगा और तभी कुछ कर सकने में हम मजदूर सबल होंगे।

हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि मैनेजमेन्ट और सरकार एक ही परिवार के दो नाम हैं। तीसरी शक्ति अर्थात मजदूर विरोधी तत्व जब खरीद लिया जाता है तो मजदूर का सत्यानाश होने में देरी नहीं लगती। खोखले नारों, गर्म भाषणों घरनों, भूखहड़तालों इत्यादि से कुछ नहीं बनता। मजदूरों को कुछ दिलाने के बदले उनके दिलों तथा दिमागों को बदलना होगा। सत्य और असत्य के अन्तर को परखना होगा।

ओरियन्ट फैन में तालाबन्दी

प्लान्ट नम्बर ११, सैक्टर ६ स्थित ओरियन्ट जनरल इन्डस्ट्रीज पंखे बनाने वाली जानी-मानी कम्पनी है। कुछ समय पहले ओरियन्ट मजदूरों ने रिकार्ड प्रोडक्शन किया और ४ जून को सालाना एग्रीमेंट के लिये मैनेजमेन्ट को माँग-पत्र दिया। गोदामों में माल और आफ सीजन की शुरूआत—मजदूरों को और दबाने के लिये तालाबन्दी का हथियार इस्तेमाल करने का बढ़िया मौका था। पहली सितम्बर से ओरियन्ट मैनेजमेंट ने फैक्ट्री में लाकआउट कर दिया।

ओरियन्ट मैनेजमेंट ने धीरे-धीरे अपनी सभी एनसीलरीज बन्द की और लाकआउट से कुछ दिन पहले से वरकरों को मैटेरियल कम देना शुरू कर दिया था। इन तथ्यों से साबित होता है कि मैनेजमेंट ने तालाबन्दी सोच-समझ कर, तैयारी करके की है।

ओरियन्ट फैन में ठेकेदारी-प्रथा काफी ज्यादा है। कैजुअल वरकर भी ओरियन्ट में बहुत हैं। इन मजदूरों को हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन तक नहीं दिया जाता। तालाबन्दी वाले दिन से ही इन सब मजदूरों की नये काम के लिये भाग-दौड़ शुरू हो गई।

परमानेन्ट मजदूरों का भी ओरियन्ट फैन में बुरा हाल है। बीस-बाइस साल पुराने मजदूरों की तनखा भी तेरह सौ रूपयों से ज्यादा नहीं है।

तालाबन्दी के खिलाफ कारगर कदम उठाने के लिये ओरियन्ट फैन के मजदूरों को ऊपर चर्चित हालात को भी ध्यान में रखना होगा ! साथ ही, इन मजदूरों को केल्विनेटर-थामसन प्रेस-हितकारी पाट्रीज-अमेटीप मशीन टूल्स-अल्फा टोयो-आदि-आदि में तालाबन्दियों के अनुभवों पर भी विचार करना चाहिये। कुछ बातें साफ हैं—फैक्ट्री गेट पर ताश खेलने, डी एलसी-डी सी-मन्त्रियों को दरखास्तें देने और समझौता वार्ताओं के ड्रामों की पिटी-पिटाई राहों से ओरियन्ट फैन के मजदूरों को नुकसान के सिवाय और कुछ हासिल नहीं होगा। जरूरत ऐसे कदम उठाने की है जिनसे मजदूर पक्ष की ताकत बढ़े। ऐसा एक कदम हर रोज जलूस निकालना है। ओरियन्ट फैन के मजदूरों के परिवारों और अन्य फैक्ट्रियों के मजदूरों का इन जलूसों में शामिल होना तालाबन्दी के खिलाफ माहौल बनाने में बहुत मददगार होगा। यह ध्यान में रखने की जरूरत है कि जलूस हर रोज निकालने से ही बात आगे बढ़ेगी, चाहे आधे घन्टे के लिये सुबह आठ से साढे आठ बजे तक ही जलूस निकालें। महीना-बीस दिन में एक बार जलूस निकालना ताकत बढाने की बजाय रस्म पूरी करने समान होता है, इससे मजदूरों को कोई खास फायद नहीं होता। ओरियन्ट फैन के मजदूरों ने तालाबन्दी के खिलाफ ताकत बढाने वाले कदम फौरन उठाने शुरू नहीं किये तो लाकआउट जितना लम्बा खिंचता जायेगा उतनी ही मजदूरों की ताकत बिखरती जायेगी, मजदूर पक्ष कमजोर पड़ता जायेगा।

डिसमिस वरकर

डिसमिस होते ही किसी मजदूर की समस्यायें बहुत बढ़ जाती हैं। इधर कुछ समय से ढेरों में केसों को चन्डीगढ़ से लेबर कोर्ट को रेफर नहीं किया जा रहा। इस प्रकार लेबर कोर्ट में केस को लाने तक के लिये ऐसे मजदूरों के लिये हाई कोर्ट जाना जरूरी किया जा रहा है। डिसमिस किये गये वरकरों के लिये यह एक और बड़ी परेशानी खड़ी की जा रही है। डिसमिस वरकरों की इस बात में वजन है कि भेंट-पूजा के जरिये मैनेजमेन्टें चन्डीगढ़ से केस रेफर नहीं होने दे रही क्योंकि वे जानती हैं कि हाई कोर्ट के खर्च से डर कर डिसमिस किये वरकर चुपचाप हिसाब ले लेंगे। इससे फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर और डर जायेंगे।

डिसमिस वरकरों की गिनती तो फरीदाबाद में कई हजार में है ही, ऐसे मजदूरों की संख्या भी बहुत है जिनको डिसमिस हुये साल-दो साल ही हुये हैं और जिनके केस लेबर कमीश्नर ने चन्डीगढ से रेफर नहीं किये हैं। कभी किसी यूनियन के दफ्तर में, कभी किसी वकील के यहाँ, कभी डी एल सी के दफ्तर में और कभी मन्त्रियों के चक्कर लगाते वक्त इस तरह से परेशान मजदूर एक-दूसरे के सम्पर्क में आते हैं। इस सिलसिले में डिसमिस वरकरों ने संगठित हो कर अपनी समस्याओं से जूझने के लिये कदम उठाये हैं। अलग-अलग फैक्ट्रियों के डिसमिस किये गये वरकरों से सम्पर्क और रेगुलर मीटिंगों में विचार-विमर्श करके कदम उठाने का सिलसिला इन मजदूरों ने शुरू कर दिया है। २३ अगस्त की इनकी मीटिंग में स्कार्टटोन के बल्स-ईस्ट इंडिया काटन मिल्स-केल्विनेटर-सुरभि इन्डस्ट्रीज के डिसमिस वरकर शामिल हुये।

लुधियाना कपड़ा मजदूर

रेडियो-टी वी-पत्र-पत्रिकाओं में पँजाब में मजदूर आन्दोलनों की चर्चा कम ही होती है। अबोहर में कपड़ा मजदूरों पर पुलिस फायरिंग कोने की न्यूजों में दब गई थी। इधर लुधियाना में टैक्सटायल वरकर आन्दोलन की राह पर हैं। सामग्री हमने पँजाबी पत्रिका "इन्कलाबी जनतक लीह" से ली है।

लुधियाना की अलग-अलग कपड़ा मिलों के हजारों मजदूरों ने अगस्त में अपनी डिमान्डों के लिये साँझा आन्दोलन शुरू कर दिया। इन मजदूरों की डिमान्डें हैं.— १) पक्के रजिस्टर पर हाजिरी लगाई जाये, २) न्यूनतम वेतन कानून पर अमल किया जाये, ३) बरसों से लगातार काम कर रहे मजदूरों को पक्का किया जाये, ४) ई एस आई लागू की जाये, ५) प्रोविडेन्ट फन्ड जमा किया जाये, ६) महँगाई के आंकड़ों पर अमल किया जाये।

टैक्सटाइल मजदूरों की यह डिमान्डें सरकार के लेबर कानूनों को लागू करने के दायरे में हैं। पँजाब के लेबर मिनिस्टर लुधियाना में मैनेजमेंटों से मीटिंगें करके और मजदूरों से कानूनों को लागू करने का वायदा करके चलते बने हैं। लुधियाना में ई एस आई, प्रोविडेन्ट फन्ड और लेबर डिपार्टमेन्ट के लोग तो बस त्यौहारों पर "गिफ्ट" लेने में ही माहिर हैं।

लुधियाना के कपड़ा मजदूरों ने आन्दोलन की राह पर कदम बढाये ही थे कि मैनेजमेंटों के फुटकर गुन्डों ने हमला करके २६ अगस्त को दर्जनों मजदूर घायल कर दिये। और पुलिस रूपी संगठित गुन्डे आन्दोलन कर रहे कपड़ा मजदूरों को थानों में बन्द करके उनसे मार-पीट कर रहे हैं। लेकिन अपनी डिमान्डों के लिये मजदूरों का आन्दोलन जारी है।

टैक्सटाइल मजदूरों के इस आन्दोलन को वहाँ के मोल्डर और स्टील वरकरों के समर्थन की चर्चा हैं।

थर्मल में आन्दोलन

बरसों से टाइम-ब-टाइम हो रहे बिचौलियों के रस्मी और फर्जी आन्दोलनों के बाद पहली बार फरीदाबाद थर्मल पावर हाउस में एक वास्तविक मजदूर आन्दोलन की कुछ झलक दिखाई दी है। ६ अगस्त से "संयुक्त मंच" के रूप में थर्मल वरकरों की एक जनरल डिमान्ड के लिये यह आन्दोलन शुरू हुआ हैं। वैसे, अपनी दुकानदारी को फिर जमाने के लिये भिन्न-भिन्न चोलेधारी बिचौलिये भी इसमें शामिल हैं।

थर्मल मैनेजमेंट ने अंकुर रूप में ही आन्दोलन को कुचलने के लिये वरकरों में फूट डालने की कोशिश की। इसके लिये मैनेजमेंट ने रस्मी-फर्जी आन्दोलन में माहिर अपने पट्ठों की पीठ पर हाथ रखा। लेकिन बात बनी नहीं। इस पर थर्मल मैनेजमेंट ने पुचकारने का तरीका अपनाया और जिम्मेदारी बोर्ड को ट्रान्सफर करने की फिराक में हैं। साथ ही, कुछ मजबूत हो रहे मंच में तोड़-फोड़ की कोशिश भी जारी है—२७ अगस्त की गेट मीटिंग में यह साफ-साफ दिखाई दिया।

आन्दोलन में आम मजदूरों की बढ़ती सक्रियता तथा साइड मीटिंगों में खुला विचार-विमर्श मैनेजमेंट और बिचौलियों, दोनों से निपटने की एक राह है।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेर सिंह के लिए उत्तरांचलप्रिन्टर्स, फरीदाबाद से मुद्रित